



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2000/आश्विन 14, 1922

No. 133]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2000/ASVINA 14, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2000

सं. टीएएमपी/59/99-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार केपीटी में स्थायी जेट्टी का निर्माण करने के लिए कण्डला पत्तन न्यास (केपीटी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप देने से संबंधित मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड और मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त अभ्यावेदन को निपटाता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/59/99-केपीटी

मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी)

और

मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)

}

..... आवेदक

बनाम

कण्डला पत्तन न्यास (केपीटी)

..... प्रतिवादी

आदेश

(सितम्बर, 2000 के 26वें दिन पारित किया गया)

यह मामला केपीटी में स्थायी जेट्टी का निर्माण करने के लिए कण्डला पत्तन न्यास (केपीटी) के साथ एमओयू को अंतिम रूप देने से संबंधित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के संयुक्त अभ्यावेदन से संबंधित है।

2. यह अभ्यावेदन केपीटी को टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। केपीटी की दृष्टि में यह प्राधिकरण द्विपक्षीय करार से संबंधित इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें प्राधिकरण का उल्लिखित पक्ष है कि वह इससे बोली दस्तावेज को अंतिम रूप देने के समय से संबद्ध हो सकता है, इसलिए बोली दस्तावेज, एमओयू, करार आदि में संपन्न कार्य के कारण उसके चिन्ते को सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में, इस प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि आईओसी और बीपीसीएल के संयुक्त अभ्यावेदन पर आगे औपचारिक 'मामले' के रूप में कार्रवाई की जाए।

3. इस मामले पर कण्डला में 7 मार्च, 2000 को संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। आईओसी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के इस संयुक्त सुनवाई में उपस्थित होने में आने वाली अपरिहार्य परिस्थितियों को उद्धृत करते हुए इसके स्थगन का अनुरोध किया था। यह मामला इस निदेश के साथ स्थगित कर दिया गया था कि तेल कम्पनियों और केपीटी के बीच बाताचीत में हुई आगे की प्रगति, जिसके बारे में बताया गया था कि प्रगति हो रही है, के बारे में आईओसी से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

4. तत्पश्चात्, आईओसी द्वारा इस प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था कि इस पूर्व प्रत्याशित अवस्था में इस संयुक्त अभ्यावेदन पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए। इन लंबित मुद्दों को उनके और केपीटी के बीच परस्पर बातचीत द्वारा निपटा लिया जाएगा।

5.1 आईओसी और बीपीसीएल से पांच माह से अधिक समय तक सूचना प्राप्त न होने पर इस प्राधिकरण ने अगस्त, 2000 में वर्तमान प्रगति की सूचना 15 सितम्बर, 2000 तक देने का अनुरोध किया था। ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि वे अभ्यावेदन को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं थे।

5.2 आईओसी ने सूचित किया है कि यह मामला उनके और केपीटी के बीच आकस्मिक बातचीत से निपटा लिया जाएगा और इस समय टीएएफपी से कोई सहायता अपेक्षित नहीं है। बीपीसीएल ने अनुबंधित समय सीमा में कोई उत्तर नहीं दिया है। अतः बीपीसीएल का आशय अभ्यावेदन को आगे बढ़ाने का नहीं है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में इस प्राधिकरण ने मामले को वापस लिया गया मामले हुए बंद करने का निर्णय लिया है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/143/2000/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2000

No. TAMP/59/99-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation jointly made by M/s. Indian Oil Corporation and M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited about finalisation of MOU with the Kandla Port Trust (KPT) for construction of a permanent jetty at the KPT, as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/59/99-KPT

M/s. Indian Oil Corporation Limited

and

M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited

}

Applicants

v/s

The Kandla Port Trust (KPT)

Respondent

ORDER

(passed on this 26th day of September 2000)

This case relates to a representation jointly made by the Indian Oil Corporation Limited (IOC) and the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) about finalisation of an MOU with the Kandla Port Trust (KPT) in connection with construction of a permanent jetty at the KPT.

2. The representation was referred to the KPT for comments. The KPT has been of the view that this Authority cannot intervene in the matter which pertains to a bilateral agreement. It has been the stated view of this Authority that it may be associated from the time of finalisation of the Bid Document itself so that its discretion would not be circumscribed by having to contend with *fait accompli* in Bid Document, MOU, Agreement, etc. That being so, this Authority then decided that the joint representation made by the IOC and the BPCL should be processed further formally as a 'case'.

3. The case was taken up for a joint hearing on 7 March 2000 at Kandla. The IOC requested for an adjournment citing unavoidable circumstances coming in the way of its senior officer attending the joint hearing. The case was accordingly adjourned with the direction that it would be heard after receipt of intimation from the IOC about the further developments in the negotiations between the Oil Companies and the KPT which were reported to be in progress.

4. The IOC subsequently requested the Authority not to take any further action on the joint representation at this stage as it anticipated that the pending issues would be settled mutually between them and the KPT.

5.1 Since nothing was heard from the IOC and the BPCL for more than five months, the Authority requested, in August 2000, to intimate the present developments by 15 September, 2000, failing which it would be presumed that they were not interested to pursue the representation.

5.2 The IOC has informed that the matter will be mutually settled between them and the KPT; and, it does not require any assistance at the moment from the TAMP. The BPCL has not responded within the stipulated time limit and hence their intention of not pursuing further with the representation is presumed.

6. In the result and for the reasons given above, the Authority decides to close this case as withdrawn.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT/III/TV/143/2000/Ext'y.]